



OK

भारत का यज्ञपत्र

The Gazette of India

प्राधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1992/चत्र 10, 1914

No. 220] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1992/CHAITRA 10, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Fusing is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेदन

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1992

का. आ. 250(अ)/18कक आई. डी. आर. ए./92—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विभाग) के प्रदिव्य सं. 320(अ)/18कक/आईडीभारए/79 मार्चिय 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें उल्लिखित उक्त आवेदन कहा गया है) मेसर्से अपोलो जिप्पर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपकरण का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की द्वारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह नारीय भी मन्महित है, तीन वर्ष की प्रवधि

के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, बख्त और और रूण उद्योग, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, प्रशिक्षण बंगल सरकार को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करते के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय हाते पर कि लोकहित में यह समर्थन है कि उक्त आदेश तांत्रिक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1992 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए इसे जारी रखने के लए समय-समय पर निर्देश जारी किया गया थे। [दिविंग भारत सरकार के उद्योग बंगलालय] (औद्योगिक विकास विभाग)] के प्राप्तेः

स का आ 246(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /32, तारीख 15 मई, 1987

सं. का आ 822(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /82, तारीख 24 नवम्बर 1982,

स का आ 385(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /83, तारीख 31 मार्च, 1983,

सं का आ 872(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /83, तारीख 30 नवम्बर, 1983,

स का आ 472(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /84, तारीख 28 जून, 1984,

स का आ 976(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /34, तारीख 29 दिसम्बर, 1984,

सं. का आ 275(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /85, तारीख 29 मार्च, 1985,

स का आ 148(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /86, तारीख 31 मार्च, 1986,

सं का आ 266(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /87, तारीख 30 मार्च, 1987,

सं का आ 326(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /88, तारीख 30 मार्च 1987

स का आ 247(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /89, तारीख 31 मार्च, 1989

सं का आ 277(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /90, तारीख 30 मार्च, 1990 और

स का आ 214(अ)/18कक/प्राई डी आर ए /91, तारीख 30 मार्च 1991,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीक्षित है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1993 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि में प्रभावी बना रहे।

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (195 ला 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के नाथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रवल्ल शक्तियों का ग्रहण करते हुए यह निर्देश देता है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1993 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[का स 2/23] 80 - ८। यू एस]
एन आर कृष्णन, अपर मन्त्री

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1992

S.O. 250(E)|18AA|IDRA|92 :—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of Sub-section (1) of Section 18AA of the Industries Development & Regulation Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking ;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1992 [Vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)].

Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982,

S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82, dated the 24th November, 1982,

S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st March, 1983,

S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983,

S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984,

S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985,

S.O. 146(E)|18AA|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,

S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,

S.O. 326(E)|18AA|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,

S.O. 247(E)|18AA|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,

S.O. 277(E)|18AA|IDRA|90, dated the 30th March, 1990, and

S.O. 214(E)|18AA|IDRA|91, dated the 26th March, 1991,

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1993 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2), of Section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Orders shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1993.

[F. NO. 2(23)|80-CUS]

N. R. KRISHNAN, Addl. Secy.